

मसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग **II**—-खण्ड 3—-उपक्रण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]

नई बिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1970/फाल्गुन 16, 1891

No. 51].

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1970/PHALGUNA 16, 1891

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि ह झलग संकलन के कप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March 1970

- G.S.R. 423.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 371 of the Constitution, the President hereby makes, with respect to the State of Andhra Pradesh, the following Order further to amend the Andhra Pradesh Regional Committee Order, 1958, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Regional Committee (Amendment) Order, 1970.
 - (2) It shall come into force on the 9th day of March, 1970.
- 2. In paragraph 7 of the Andhra Pradesh Regional Committee Order, 1958 (hereinafter referred to as the "principal Order"), for the words "does not involve any financial commitment other than expenditure of a routine and incidental character" the words "is in conformity with the over-all financial arrangements contemplated in the annual budget or in the Five Year Plan pertaining to the Telengana region" shall be substituted.

- 3. After paragraph 10 of the principal Order, the following paragraphs shall be inserted, namely:—
 - "11. The Governor shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President on the working of the Regional Committee.
 - 12. The State Government shall forward to the Regional Committee halfyearly reports of the progress of action taken on the recommendations made by the Regional Committee.
 - 13. The State Government shall forward to the Regional Committee periodical reports giving the progress of implementation of Central Government's decisions in matters relating to the integration of the Services in the State consequent on the States reorganisation in 1956."
 - In the First Schedule to the principal Order,—
 - (1) for item 3, the following item shall be substituted, namely:
 - "3. Primary, secondary and university education.";
 - (2) for item 7, the following item shall be substituted, namely:—
 - "7. Cottage, small-scale, medium and heavy industries falling under entry 24 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution."; and
 - (3) for item 9, the following items shall be substituted, namely:
 - "9. Development and economic planning within the plan allocations for the Telengana region as formulated by the State Legislature.
 - 10. Methods of recruitment, and the principles to be followed in making appointments to subordinate services and posts (that is to say, services and posts appointments to which are not notified in the Official Gazette but not including any service of tehsildars) under the State Government in the Telengana region.
 - 11. Securing provision of adequate employment opportunities to the people of the Telengana region in the State Government, quasi-Government institutions, statutory authorities and corporate bodies in the Telengana region."
 - 5. In the Second Schedule to the principal Order,-
 - (1) after item 3B, the following item shall be inserted, namely:-
 - "3-C in Chapter XVIII, in rule 154, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(1A) in the annual financial statement, details regarding the receipts and expenditure in relation to the Telengana region and rest of the State shall be shown in separate columns for facility of reference and consideration by the Regional Committee.";
- (2) in item 4, rule 164-M of Chapter XVIII-A shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and—
 - (a) in sub-rule (1) as so renumbered, for the words "does not involve any financial commitment other than expenditure of a routine and incidental character", the words "is in conformity with the over-all financial arrangements contemplated in the annual budget or in the Five Year Plan pertaining to the Telengana region" shall be substituted;
 - (b) after sub-rule (1) as so renumbered the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(2) The Chairman of the Regional Committee or. in his absence, any member of the Regional Committee shall lay before the Assembly—
 - (a) a copy of every resolution referred to in sub-rule (1) as soon as may be after it is passed and forwarded to the State Government;
 - (b) a copy of the report, if any, of the Regional Committee or a subcommittee in the matter;

- (c) a periodical report showing the action taken by the State Government on such resolutions together with the views of the Regional Committee."
- 6. In the Third Schedule to the principal Order, in rule 8-A inserted by clause (ii), for the words "the matter shall be referred by the Chief Minister to the Governor" the words "the Chief Minister shall first endeavour to arrive at an agreed conclusion by discussion with the Chairman of the Regional Committee and in default of such agreement, refer the matter to the Governor" shall be substituted.

[No. F. 22/21/69-SR.]

L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1970

सा० का० नि० 423:—संविधान के अनुक्छेद 371 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक समिति आदेश, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए भांध्र प्रदेश राज्य के बारे में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, प्रर्थातु:——

- 1. (1) यह मादेश मांध्र प्रदेश प्रादेशिक समिति (संशोधन) मादेश, 1970 कहा जा सकेगा ।
 - (2) यह मार्च 1970 की 9 तारीख के विन को प्रवृक्त होगा।
- 2. मां प्र प्रदेश प्रादेशिक समिति भ्रादेश, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल म्रादेश" कहा गया है) "भीर विधायी या कार्यपालिका कार्यवाई में नेमी भीर म्रानुषंगिक स्वरूप के व्यय से भिन्न कोई वित्तीय वायदा अन्तविलत न हो" शब्दों के स्थान पर "भीर विधायी या कार्यपालिका कार्यवाई तेलंगाना प्रदेश सम्बन्धी वार्षिक बजट में या पंच वर्षीय योजना में अनुष्यात व्यापक वित्तीय प्रबन्धों के अनुरूप हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - 3. मुल भावेश के पैरा 10 के पश्चात् , निम्नलिखित पैरा भ्रन्त:स्थापित किया जाएगा, भ्रयात् :--
 - "11. राज्यपाल प्रविवर्ष, या जब कभी राष्ट्रपति ऐसा ग्रपेक्षित करें, प्रावेशिक समिति के कार्यकरण के विषय में; राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा"।
 - 12. प्रादेशिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाई की प्रगति की धर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, राज्य सरकार प्रावेशिक समिति को भेजेगी।
 - 13. 1956 में राज्यों के पुर्ने स्संगठन के परिणामस्वरूप राज्य की सेवाथ्रों के एकीकरण से सम्बद्ध विषयों के बारें में केन्द्रीय सरकार के विनिष्चयों के क्रियान्वयन की प्रगति बनाते हुए, राज्य सरकार प्रादेशिक समिति को कालिक रिपोर्ट भेजेगी।"

- 4. मूल झावेश की प्रथम अनुसूची में,---
- (1) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, श्रर्थात् :---
 - "3. प्राथमिक, माध्यमिक भौर विश्वविद्यालय शिक्षा।"
- (2) मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, ग्रयात् :---
- "7. संविधान की सप्तम श्रनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के श्रन∃र्गत श्राने वाले कुटीर, लघु, मध्यम श्रीर भारी उद्योग," श्रीर
- (3) मद 9 के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, ग्रर्थात् :---
 - "9. राज्य विधान मण्डल द्वारा यथासूत्रित तेलंगाना प्रदेश के लिये योजना भावटन के भीतर विकास भौर भाषिक योजना ।
 - 10. तेलंगाना प्रदेश में राज्य सरकार के घ्रधीन घ्रधीनस्य सेवाघों घीर पदों पर (घ्रयात् उन सेवाघों घीर पदों पर जिनपर की नियुक्तियां शासकीय राजपत्न में घ्रधिसूचित नहीं होती हैं किन्तु इसमें तहसीलदारों की सेवा सम्मिलित नहीं है) नियुक्तियां करने में घ्रपनायी जाने वाली भर्ती की पद्धतियां घौर सिद्धान्त ।
 - 11. तेलंगाना प्रदेश में राज्य सरकार, अर्धसरकारी संस्थाओं, कानूनी प्राधिकरणों और निगमित निकायों में तेलंगाना प्रदेश के लोगों के लिए पर्याप्त नियोजन के अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।"
- 5. मूल धादेश की द्वितीय धनुसूची में,---
- (1) मद 3 ख के पश्चात् निम्नलिखित मद ग्रन्तःस्यापित की जाएगी, ग्रर्थात् :---
 - "3-ग ब्रध्याय 18 में, नियम 154 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, ग्रथीत् :—
 - "(1क) वार्षिक वितीय विवरण में तेलंगाना प्रदेश और शेष राज्य के बारे में आय और व्यय सम्बन्धी व्यौरे प्रादेशिक समिति द्वारा देखे जाने वाले विचार करने की सुविधा के लिए पृथक स्तम्भों में दिशत किए जाएंगें।"
- (2) मच 4 में, भ्रष्ट्याय 18-क के नियम 164-ड को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा भौर---
 - (क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (1) में "और विधायी कार्यपालिका कार्यवाई में नेमी भीर भ्रानुषंगिक स्वरूप के व्यय से भिन्न कोई वित्तीय वायदा भ्रन्त वंलित न हो।" शब्दों के स्थान पर " भ्रौर विधायी या कार्यपालिका कार्यवाई सेलंगाना प्रदेश सम्बन्धी वार्षिक बजट में या पंचवर्षीय योजना में भ्रनुध्यात व्यापक वित्तीय प्रवन्धों के भ्रनुरूप हों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (आ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम प्रन्तः स्थापित किया जाएगा, प्रार्थातः :—
 - "(2) प्रादेशिक समिति का ग्रध्यक्ष या उसकी ग्रनुपस्थित में; प्रादेशिक समिति का कोई सदस्य सभा के समक्ष निम्नलिखित रुक्रेगा :---
 - (क) उप-नियम (1) में निर्विष्ट प्रत्येक संकल्प की, उसके पारित किए जाने और राज्य सरकार को भे ने जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र एक प्रति ;
 - (ख) यदि उस विषय में प्रादेशिक समिति या किसी उप-समिति की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी एक प्रति ;
 - (ग) ऐसे संकल्पों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाई भौर उसके साथ प्रादेशिक समिति के विचार वर्णित करने वाली एक कालिक रिपोर्ट ।"
- 6. मूल श्रावेश की तृतीय श्रनुसूची में, खण्ड (ii) द्वारा श्रन्तःस्थापित नियम 8-क में, "वह विषय मुख्य मंत्री द्वारा राज्यपाल को निर्दिष्ट किया जायगा" शब्दों के स्थान पर " मुख्य मंत्री पहले प्रावेशिक समिति के श्रव्यक्ष के साथ विचार विमर्श द्वारा करार पाए, गए परिणाम पर पहुंचने का प्रयास करेगा श्रीर ऐसे करार के श्रभाव में उस विषय को राज्यपाल को निर्दिष्ट करेगा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

[सं० फा० 22/21/69-रा० पु०]

ल० प्र० सिंह, सचिव,

-1